



### पृष्ठ १ का शेष भाग.....

और शहीदी क्षेत्रों में महिलाओं के दुर्व्यवहार की विशिष्ट प्रकृति के क्षेत्रों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए वे दूर्स्थ गांवों तक पहुँचने में समर्पण होनी चाहिए। पुलिस बल में अधिक से अधिक महिलाओं की मौजूदगी एक निवारक के रूप में भी काम करने में सहायता होगी।

**क्या आपको लगता है कि कानून को, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और महिलाओं के लिए न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है?** दिसंबर २०१२ में दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ हुए मर्याद बलात्कार की घटना के बाद, सरकार ने कानून में संशोधन करके महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को परिमाणित किया जो पहले महिलाओं के शील भंग करने जैसे व्यापक दायरे में परिमाणित किया जाता था। यौन प्रताड़ना के दौरान विभिन्न प्रकार की बर्ता के लिए शामिल करने की भी परिमाणित किया गया। स्टॉकिंग, दशनरप्ति, यौन प्रताड़ना, अति निकृष्ट यौन प्रताड़ना, तेजाब से हमला को भी विधिक शब्दावलि में सम्भिलित किया गया है। बलात्कार के कारण मृत्यु, बलात्कार के कारण पीड़िता को निष्फलीय अवस्था में पहुँचाना, सामूहिक बलात्कार, एक सिद्धांती द्वारा बलात्कार, हिरासत में बलात्कार, सांप्रतायिक दिसा के दौरान बलात्कार आदि की भी गिनती की गई है। अब बढ़े हुए दण्ड का प्रावधान है। प्रक्रियात्मक रूप से अब यह अनिवार्य है कि महिला के विरुद्ध अपराध की एक आई. आर. महिला पुलिस दर्ज करें, एफ.आई.आर. दर्ज करने की भी वीडियोग्राफी की जाए। जांच के दौरान महिला ही बयान दर्ज करें, पीड़िता का परामर्श और पैरा लीगल सलाह प्रदान करें और पीड़िता को विकित्तीय जांच के लिए ले जाए और बयान के लिए भजिस्ट्रेट के पास ले जाए। एक महिला पुलिस अधिकारी को महिला पीड़ित के दर्द को सुनने और अपराधिकारियों को पूछा करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि पीड़िता को अपनी व्यथा किसी पुरुष अधिकारी को सुनाने में शर्मिंदगी न महसूस हो। इससे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की ज़ल्दत पड़ती है।

**पुलिस में महिलाओं की भूमिका के बारे में यदि आप कोई विशेष विचार व्यक्त करना चाहें?**

हमें एक समाज के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए की इस राष्ट्र की महिलाएं अपने सीमांत में स्थायी को सुरक्षित महसूस करें। हम उस देश के लोग हैं जिन्होंने स्थायी को भारत के संविधान को समर्पित कर दिया है और इसकी शपथ लेते हैं, इसलिए देश की महिलाओं के लिए शान्तिक और वैचारिक रूप में वास्तविकता बनानी चाहिए जो आज भी सामनात और आदर का भी समय तथा किसी भी स्थान पर शोषण के भय से स्वतंत्र होने की प्रतीक्षा कर रही है। इसके लिए हमें दूसरा पुलिस बल को मजबूत करना होगा, उसी समान समर्पण पुलिस बल में वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए भी उत्तिक कदम उठाने होंगे, ताकि वह हमें एक संवेदी, समझदार और व्यवाधायिक बल प्रदान करें। विशित परिवर्तन लाने के लिए शायद इस राष्ट्र के लिए पुलिस में उत्तिक सुधार लाने की आवश्यकता को महसूस करने का यह उत्तिक समय है।

## यह क्यों होता है?

महिलाओं का यौन शोषण कैवल आरोपी के द्वारा नहीं होता है, बल्कि वह तब भी शोषित होती है। जब वह इसकी शिकायत करने जाती है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं।

मध्य प्रदेश के खांडवा ज़िले के मोघट थाने में एक महिला कांस्टेबल के साथ थाना इंचार्ज रविन्द्र यादव ने ९४ फरवरी को कामकातापूर्ण छेड़छाड़ किया जिसे एक दिन पहले ही उस थाने से हस्तांतरित कर दिया गया था।

३० वर्षीय महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि जब वह शाम को घर के लिए निकल रही थी तब यादव ने थाने के एक कमरे में उसे बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद करके उसके साथ बदतमीजी की हालांकि, उसने उसे रोकने का भी प्रयत्न किया जो व्यर्थ गया। महिला थाने की जांच अधिकारी सुनीता रावत ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यादव उसे कुछ समय से यातना दे रहा था और उस दिन उसके साथ छेड़खानी की तब उसके गाई ने उसे वहां से बताया। हालांकि, ४० वर्षीय यादव को एक दिन पहले ही हस्तांतरित कर दिया गया था

लेकिन कुछ कार्यों को निपटाने के बहाने से वह उस दिन वहां रह गया था। क्योंकि, यादव के लिए यह अनिवार्य नहीं था कि हस्तांतरण के बाद वह तुरंत जगह खाली कर देता।

जांच अधिकारी के अनुसार उन्होंने पीड़िता, उसके भाई और एक अन्य महिला का बयान दर्ज कर लिया था और द.प.स. की धारा १६४ के अंतर्गत पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाना था कैवल तभी यादव के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती। पीड़िता जिसको दो बेटियां हैं, उसे यह नौकरी उसके पति की मृत्यु के बाद सहानुभूति के आधार पर प्राप्त हुई थी। पुलिस ने यादव के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलंब किया लेकिन परिवर्जनों और रथानीय लोगों तथा आग आत्मीय पार्टी के सदस्यों द्वारा थाने के बाहर प्रदर्शन करने पर उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर लिया गया।

एक अन्य घटना में एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद शिक्षक स्कूल में शराब पीकर आता है। एक अन्य घटना में एक लड़के ने युवती की फोटो को किसी अश्लील फोटो में जोड़कर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की जब पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गई तो थाना प्रभारी ने कहा 'तुम सभी लड़कियां इसी प्रकार की हो जो'। अर्थात् जिसने उस लड़की की अश्लील फोटो बनाई उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय उसे शिकायत करने आना भी गवारा नहीं।

एक अन्य घटना में महाराष्ट्र के ए.डी.जी. स्टर के आई.पी.एस. अधिकारी के विरुद्ध उनकी एक ३२ वर्षीय महिला कर्मचारी ने कोलाबा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि ७७ फरवरी को उसके बॉस ने दक्षिणी मुंबई के उनके

### पृष्ठ १ का शेष भाग.....

या जनता /समुदाय से। आंतरिक स्तर पर महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पहला कदम है कठोर और स्पष्ट नीति जिसके बारे में सबको जानकारी हो। आपको एक निर्णय लेना होगा कि अपने बल में आप इस नीति को कदमपि सहन नहीं करेंगे और यह निर्णय लिखित रूप में होना चाहिए। एक ऐसी नीति जो स्वीकृत हो और वाह वह आंतरिक उपयोग के लिए हो फिर भी यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो और बल में शीर्ष से लेकर तले तस्वीर सबको इसकी जानकारी हो कि या तो आप इसे अपनायेंगे या फिर इसकी अवहेलना के लिए उत्तर दण्ड पाएंगे। इसके आलावा, पूरी कार्य संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि नीतियों से विचार नहीं बदलते उसे तो रख्य बदलना होता है। जैसे विशासा विशा-निर्देश है, आप केवल उसे दीवारों पर टांग कर माहौल नहीं बदल सकते। पुलिस को अपनी संस्कृति बदलने की आवश्यकता है। पुलिस यह नहीं कह सकती कि पुलिस भी

तथा एवं आंकड़े	
देश भर में क्षेत्रों की संख्या	बलात्कार
अपहरण	बलात्कार
२०१४	२८,६०७
२०१३	५९,८८९
२०१२	२८,२६२
२०११	३५,५६५
कुल	९,६४,६९५
२०१३ में अपराधीयां	२०१३ में अपराधीयां
दर १० : आ।	दर १० : आ।
सौनायः न्यू इंडियन एक्सप्रेस डॉक कोम,	१ मार्च २०१५

हम, लोक पुलिस के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, लोक पुलिस में प्रकाशित करें। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।



शक्तियों द्वारा यौन शिकायत पर महिला पुलिस की अवरिक स्तर पर उनके रूप से सुनवाई और कार्यवाही पहला कदम है।

शिक्षक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३४, ३४ के तथा ब्लैकमेल करने वाले लड़के के विरुद्ध धारा ५०८ के विरुद्ध शिकायत दर्ज करके जांच शुरू करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस शिकायतकर्ता को ही अपमानित करने का प्रयत्न करनी चाहिए।

जो पुलिस आप जनता के यौन शोषण की शिकायत नहीं दर्ज करना चाहती वह अपने ही विवाद के क्षेत्र में विरुद्ध धारा ५०८ के विरुद्ध शिकायत करने के लिए महिलाएं दर्ज करती हैं। जबकि दोनों महिलाएं जिनका यौन शोषण उनके विरुद्ध अधिकारियों द्वारा किया गया था, वह महिलाएं न केवल एफ.आई.आर. दर्ज करना सकती थीं बल्कि, जैसी आशा करना ही शायद गलत है। जबकि दोनों महिलाएं जिसने यौन शोषण के बारे में लिखित शिकायत कराई है, वह महिलाएं न केवल एफ.आई.आर. दर्ज करना सकती थीं बल्कि, एसी आशा करना ही शायद गलत है। अर्थात् जिसने यौन शोषण के बारे में लिखित शिकायत कराई है, वह महिलाएं न केवल एफ.आई.आर. दर्ज करना सकती थीं बल्कि, एसी आशा करना ही शायद गलत है। आखिर ऐसा क्यों होता है?

— जीनत मलिक

(सौनायः एन.डी.टी.वी. न्यूज रिपोर्ट, १५ फरवरी तथा इंडियन एक्सप्रेस डॉक कॉम, १६ फरवरी, २०१५)

नोट — जब आप अपने आस-पास ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां आपके विरुद्ध अधिकारी ही कानून के पारे बातें करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ अवश्य बांटें।

# क्या आप जानते हैं?

इस भाग के अंतर्गत, २४-२८ फरवरी २०१४ को गुहाटी में आयोजित 'उठे पुलिस' में महिलाओं के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस' में दो गई शिफारिशों को पाठकों के सूचना के लिए ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जा रहा है।

/कंप्यूटर, परामर्श देना, विशेष अपराधों जैसे घेरेनु हिसा, यौन उत्पीड़न, किशोर, मानव तस्करी की जांच और सुरक्षा एकत्रित करने पर उनका विशेष ध्यान निर्णय।  
(ii) समता स्थापित करने के लिए विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना - करियर नियोजन (वर्तनित अधिकारियों को ५ वर्ष की विशेष/अंगिक दस्तूरी)। ऐख्येटिक फैदरेष्ट/खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमों के अनुसार अलग शारीरिक मानदण्ड/खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमों के अनुसार अलग शारीरिक मानदण्ड, आत्म शिक्षा और ऊँची शिक्षा, विशेष विश्राम गृह, शौचालय और शिशु सदन।  
(iii) महिलाओं के लिए नौँडल अफसर - उचित स्तरीय वरिष्ठ, महिलाओं से संबंधित अवसरों की सूचना के प्रसार और परामर्श, शिफारिशों और ए.टी.आर. पर आगे की कार्यवाही करना, कल्याण, लेखा परीक्षण और नीतियों के लिए सुझाव देना।  
(iv) पुलिस में महिलाओं के क्षमता नियम के लिए और अवसरन्नाम के विकास के लिए १५% वित्त आयोग और प्लान फैंड और आधुनिकीकरण अनुदान आवंटित किया जा सकता है।

## २. विषय : सौत में बदलाव

(i) सभी पदों के लिए लिंग के आधार पर न होकर खुली भर्ती ही जिसमें नियम के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग शारीरिक मानदण्ड हो, न्यूनतम भाग पूरा किया जा सकता है।  
(ii) यौन उत्पीड़न के लिए व्यवस्था को सांकेत करना और निगरानी करना  
(iii) सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के लिए बुनियादी एवं अन्य जॉन्डर संवेदी प्रशिक्षण  
(iv) समान करियर के अवसर।

## ३. विषय : सामाज की अवेक्षाओं को पूरा करना

(i) महिलाओं की सुरक्षा के लिए जनता की अपेक्षाएं और विधिक आवश्यकताओं को पूरा करना:  
• सभी थानों में २ महिला एस.आई. और ४ कार्स्टेबलों और मध्यम स्तरीय महिला कर्मचारियों को नियान्त्रक १० कर्मचारियों को तैयार किया जाए।  
• महिलाओं के विलोद्ध अपराधों के लिए कानून और जांच में प्रशिक्षण।  
• एस.आई. स्तर पर अधिक महिलाओं की भर्ती।  
• मीडिया को समाजने के बारे में प्रशिक्षण।  
• सभी पुलिस स्तरों के लिए जॉन्डर संवेदी प्रशिक्षण।



## शिफारिशें

### १. विषय : व्यावासायिकता और क्षमता नियमण

(i) गत समय में पुलिसिंग के मूल कार्यों में महिलाओं के सीमित अनावरण को ध्यान में रखते हुए - फैरेंसिक, आई.टी.

- संचाद कौशल में प्रशिक्षण
- विरोध प्रबंधन में प्रशिक्षण

### २. विषय : पुलिस में अधिक महिलाओं का प्रयोग

(i) भारत के ऐख्येटिक फैदरेशन/एस.ए.आई. द्वारा नियान्त्रित शारीरिक मानदण्डों के अनुसार सभी राज्यों में महिलाओं के विशेष भर्ती अधियान।  
(ii) सभी राज्यों में ९०% प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए समय सीमा २ वर्ष और ३०% प्रतिनिधित्व के लिए समय सीमा १० वर्ष है।  
(iii) पुलिस के आवास में आनुपातिक आरक्षण।  
(iv) सहायता व्यवस्था जैसे कि शिशु सदन और बाल देख रेख सुविधाओं को

अनिवार्यतः स्थापित किया जाना चाहिए, पुलिस लाइन और बटालियन/सुनिट मुख्यालय में कम से कम एक अवश्य होना चाहिए।  
(v) केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार मातृत्व और बब्लों के देखभाल अवकाश का सभी राज्यों द्वारा मानकीकरण किया जाना चाहिए।  
(vi) महिलाओं के उपयोग के उनकी संख्या के अनुपात के अनुसार अवसरन्नाम, उपरक्षण और फर्नीचरों का अनुकूलन।  
(vii) सुरक्षित वातावरण, अवसरन्नाम और नीतियां उपलब्ध कराकर प्रशिक्षित महिलाओं को रोक कर रखने पर प्राप्तिकाता होनी चाहिए।  
(viii) महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जॉन्डर के अनुसार न्यायसंगत बजट आवंटन होना चाहिए।

- प्रस्तुति: जीनत मलिक

## आपके विचार

संपादिका जी,

महिला दिवस की बधाई!

दरअसल, हमारे जैसी महिला पुलिस अधिकारियों के लिए दिल्ली के कमिशनर साहब ने द मार्च को महिला दिवस सामारोह के अवसर पर एक विशेष धोषणा की है जो हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं। इसके लिए हम लोग कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। धोषणा यह की गई है कि ४५ गहिला उप नियमिकों (एस.आई.) को पदोन्नति दी जाएंगी और उन्हें निरीक्षक का पद दिया जाएगा।

यहां ध्यान भोग बात यह है कि यह महिला एस.आई. दिल्ली पुलिस में एक ही ऐक पर २०-२२ सालों से कार्यरत हैं और अब तक पदोन्नति से उन्हें बंधित रखा गया था। जबकि, पदोन्नति दूसरे स्तरों पर की गई थी। ए.एस.आई. से एस.आई. स्तर पर और यहां तक कि हमारे जूनियर पुरुष अधिकारियों को प्रोमोशन देकर इंस्पेक्टर बना दिया गया था पर महिला एस.आई. को आगे पदोन्नति नहीं दी गई थी। कई बार अपने बाद आए अधिकारियों के अधीन उनके अधिनस्तों के रूप में भी काम करना पड़ा। ऐसे में हमारा मनोबल कैसा होगा यह विचारणीय है।

अभी इस धोषणा से हमारा मनोबल काफी बड़ा है लेकिन, वास्तविक प्रसन्नता और संतुष्टि तो इस धोषणा के कार्यान्वयन के बाद ही होती है। हम आशा और निवेदन करते हैं कि इसे अति शीघ्र कार्यान्वयन किया जाए और महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने और उनकी जांच में हमें सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया जाए।

ध्यावाद!  
महिला एस.आई.  
दिल्ली पुलिस

## दक्षिणी एशिया में महिला पुलिस - श्रीघ आने वाली अध्ययन रिपोर्ट

पुलिस सुधार पर लगातार जारी रहने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.), "दक्षिणी एशिया में महिला पुलिस" पर एक अध्ययन पूरा करने वाली है जिसमें भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान और मालदीव्स को समिलित किया गया था। क्षेत्रीय रिपोर्ट, जो जन २०१५ में प्रकाशित की जाएगी पुलिस में महिलाओं के स्तर पर कार्यक्रमों के देखती है जिसमें सभी ऐक पर उनकी वर्तमान संख्या, भूमिका और शक्तियां और उनके अनुभव जिसमें विमानीय भेद-भाव भी शामिल हैं, की जांच करती है। इसके अलावा, एक राज्यों में लक्ष्य रखा जाता है कि विशेष ध्यान देखभाल और अवकाश का अनुपात के अनुसार अवसरन्नाम, उपरक्षण और फर्नीचरों का अनुकूलन।

प्रत्येक थाने में ३ एस.आई. तथा १० महिला पुलिस कांस्टेबलों को रखने का लक्ष्य रखा है ताकि महिला डेस्क पर २४ घंटे के अन्तराल में विशेष ध्यान देखभाल और अवकाश का सभी राज्यों के अनुपात के अनुसार अवसरन्नाम, उपरक्षण और फर्नीचरों का अनुकूलन।

चारों देशों में, मालदीव्स में पुलिस में महिलाओं का सबसे अधिक १०% प्रतिनिधित्व है (२०१३, मालदीव्स पुलिस), इसके बाद आर.ए.ए.डी. (२०१४, बी.पी.आर.ए.ए.डी.), बंगलादेश ४.६३% (२०१३, बंगलादेश पुलिस) और पाकिस्तान में १% से कम (२०१३, नेशनल पुलिस ब्यूरो)। वर्तमान में, सभी क्षेत्रों में मुख्य नीतियां प्राथमिकता पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना है। भारत सरकार ने सभी राज्यों पर अपने पुलिस बल के लिए नीति तैयार करने की प्रक्रिया भी जारी की है।

महिला पुलिस के प्रतिनिधित्व तथा

प्रत्येक थाने में ३ एस.आई. तथा १० महिला पुलिस कांस्टेबलों को अपनायें जो दोनों देशों में महिला पुलिस को अति आवश्यक प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

मालदीव्स पुलिस एक बहुत नई संस्था है जो २००४ में ही मिलिट्री से अलग हुई है। बड़े हुए बल की आवश्यकताओं को रोक कर रखने पर प्राप्तिकाता होनी चाहिए।

महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जॉन्डर के अनुपात के अनुसार न्यायसंगत बजट आवंटन होना चाहिए।

यहां ध्यान भोग बात यह है कि वह इन नीतियों को अपनायें जो दोनों देशों में महिला पुलिस को सभी राज्यों में लक्ष्य रखा जाता है इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अनुपात के अनुसार अवसरन्नाम, उपरक्षण और फर्नीचरों का अनुकूलन।

यह रिपोर्ट, विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के समस्याएँ आने वाली चुनौतियों और कठिनाईयों की भी जांच करता है और यदि महिलाओं को पुलिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है तो भर्ती, हस्तांतरण, पदोन्नति, नियुक्तियों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों को संबंधित संगठनात्मक और नीति परिवर्तन पर सिफारिश करता है। जहां प्रत्येक देश में परिस्थितियां भिन्न हैं, सभी प्रांतों में एक आम विशिष्टता है - वरिष्ठ और नेतृत्व स्तरों पर महिलाओं का निम्न प्रतिनिधित्व। अधिकांश

- देवयानी श्रीवास्तव

# पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

**त्रिपुरा : महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी**

त्रिपुरा सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर एक तिहाई करने की घोषणा की है। इस प्रवेश में, वर्तमान समय में भी महिला पुलिस की भागीदारी का प्रतिशत अन्य स्थानों से बेहतर है — प्रदेश पुलिस में कुल कांस्टेबलों का ५३ प्रतिशत भाग महिला कांस्टेबल का है तथा बल में महिलाओं की भागीदारी कुल ५० प्रतिशत है।

गुरुग्रामी अजीत सरकार ने २०० नई भर्ती महिला कांस्टेबलों की पारिंग आऊट परेड में कहा, "हमारी सरकार का उद्देश्यों के प्रतिशत कार्यक्रम को बढ़ाकर ३०% करना है। ...५२ वर्ष पहले, पुलिस बल में केवल २८% महिलाओं थीं। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बल में महिला पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है।" इन ३०० महिला कांस्टेबलों को, अग्रसरता से ५५ कि.मी. दूर नरसिंहगढ़ में रिश्ते के टी.डी. सिंह पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में ३८ सप्ताह के अंतराल में ९८ विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के विषयों में एंटी इन्सर्जेन्सी, आपदा प्रबंधन और मानव अधिकार जैसे विषय सम्बलित किये गये थे।

इन महिला कांस्टेबलों (आयु१८-२७) में, ८६ जनजातीय, ३३ यूजुएट एंव पॉर्ट ग्रुजुएट महिलाएं भी जबकि पद के लिए आवश्यक योग्यता केवल दर्ती या १०वीं पास है। बल में नियंत्रण पर प्रशिक्षण महिला पुलिसकर्मियों से अवश्य ही बल को दोहरा लाप होगा— महिला केन्द्रित गांगलों से नियंत्रण में और पुलिस के साकारात्मक आवरण और व्यवहार ये जनता में विश्वास उत्पन्न होगा।

भर्ती में महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी से निःसंदेह ही किसी भी राज्य के पुलिस की छोड़ी अधिक मानवीय बनती है और जनता में, विशेषकर महिलाओं और वृद्धों का बल में विश्वास बढ़ता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पुलिस बल और राज्य सरकारों को बहुमुखी कदम उठाने की आवश्यकता है। शायद इसी लिए त्रिपुरा में, ४ समस्त महिला थानों की स्थापना की गई है तथा ५ और समस्त महिला थाने की स्थापना शीघ्र ही करने का आश्वासन भी दिया गया है।

(सौजन्यः इन डॉट न्यूज़ याहू डॉट कॉम, १६ फरवरी २०१५)

**दिल्ली पुलिस : महिलाओं को सुरक्षा तकनीकों का उपचार**

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए पहले ९ जनवरी को हिमात मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, जिसे एंड्रोइड एप्लीकेशन का उपयोग करने वाली महिलाएं अपने फोन में इंस्टॉल कर सकती हैं। इसके अंतर्गत परेशानी में यथिरोधी पुलिस और अपने परिजनों को अपने रिश्ते की जानकारी पहुंचा सकती है। दिल्ली पुलिस के 'हिमात मोबाइल ऐप' को अब तक ३० हजार महिलाओं ने डाउनलोड किया है और ५,६६० महिलाएं दिल्ली पुलिस के साथ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं।

इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर २५ फरवरी २०१९ को दिल्ली की महिलाओं को महिला दिवस के पूर्व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक और तकनीकी उपहार दिल्ली

पुलिस ने दिया।

इसके अंतर्गत महिलाएं अब जिस ऑटो या टैक्सी में सवार हो रही हैं उसकी फोटो भी 'हिमात व्हाट्स-एप' और 'हाईक, स्मार्ट फोन में एक ऐसा एप्लीकेशन है जो तुरंत सूचना मेजने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है।' को ८८०००१०६९ नंबर पर भेज सकती है। इन दोनों से किसी परी भी भेज गया ऐसे जिस पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचेगा और इसे वहाँ एक सप्ताह तक सभाल कर रखा जाएगा। यूप को किसी प्रकार की आपातकालीन रिश्तियों की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत कार्यवाही करेगी। दिल्ली के कमिशनर वस्त्री ने ऐप को लॉन्च करते हुए कहा, "इसे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दिल्ली पुलिस की कर्तव्यवद्धता को सुदृढ़ बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। हिमात व्हाट्स-एप यूप को भाग लाए जाएगा तो यहाँ कोई हाईक कार्रवाकता के कारण महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रिपोर्ट सबसे अधिक है।"

को ९००० करोड़ से बढ़ाकर २००० करोड़ करने की घोषणा का शायद अन्य राज्यों द्वारा स्वागत किया जाए पर उत्तराखण्ड पुलिस के लिए यह बेकार है क्योंकि प्रदेश पुलिस को इस काषे से अब तक कोई पैसा नहीं मिला है। हालांकि, राज्य में १०६० महिला हेल्पलाइन वल रहे हैं पर महिला सुरक्षा करने के लिए दूसरा वी.आई.पी. सुरक्षा पर तैयार रहती है। पर ऐसा पुलिस के कारण नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा पुलिस की संख्या न बढ़ाने तथा अन्य नीतिगत कारणों से है।

पिछले महीने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को महिलाओं को उचित सुरक्षा न उपलब्ध कराने के लिए फटकार लगाई थी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.टी.कैमरे (कैमरे) लगाए जाएं यदि सरकार, ओबामा की सुरक्षा ने किसी पर लॉक कर रही है। जनता में अपराधों के दर्द करने के बारे में जागरूकता के कारण महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रिपोर्ट सबसे अधिक है।

ए.एस.पी. महिला शाखा, ममता वोहरा



कमिशनर राहब! क्या बुनियादी फोन वालों के लिए भी कोई योजना है?

- सुरक्षा तो सभी की आवश्यकता है?

उनके अनुसार महिलाओं को पुलिस के व्हाट्स-एप नंबर को अपने ऐंड्रोइड फोन में जोड़ना होगा और एक छोटा से फोर्म भरना होगा और जड़ां से वह वाहन ले रही हैं, उस वाहन के फोटो के साथ उक्त नंबर पर भेजना होगा। महिलाएं चाहती हैं योग्यता के बारे में और सूचना भी जोड़ सकती हैं। अगर आवश्यकता हो तो महिलाएं परेशानी के समय इस यूप को मैसेज भी भेज सकती हैं।

इसे पी.ए.-१०० (कंट्रोल रूम) से भी संकालित किया जाएगा ताकि इगरजेसी की सूचना मिलने पर सबको नज़रीकी पी.सी.आर. वैन को वहाँ भेजा जा सके और मोबाइल पेट्रोलिंग वाहन को वहाँ भेजा जाएगा।

स्टार्ट फोन उपयोग करने वाली और विशेषकर कामकाजी महिलाओं के लिए यह ऐप उपयोगी होगा, यह आशा की जा सकती है। तेकिन, कामकाजी और सुवह तड़के तथा देर रात के घर पहुंचने वाली महिलाएं वही हैं जिन्हें मध्यम और उच्च स्तरीय वर्ग का सेवा प्रदाता कहा जाता है, यों घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं और स्मार्ट फोन रखने में वह सक्षम नहीं हैं। क्या दिल्ली पुलिस इन महिलाओं को भी ऐसी ही कोई सुविधा बुनियादी फोन में उपलब्ध करा पाएगी?

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम, १८ मार्च २०१५)

**महिला सुरक्षा पर कदम उठाने में सरकार विफल**

जहाँ चाह न हो, वहाँ कभी भी उचित राह नहीं निकल सकती। यह कथन सरकार की दिल्ली की जनता को अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था न देने के बारे में १०० प्रतिशत सात्य मालूम पड़ती है। इसके कई कारण हैं, जैसे — वेरों तो दिल्ली पुलिस को इसके वर्ग के बजट अवंटन में ४५२.५८ करोड़ रु. की तुलना में

इस वर्ष ५०२७.६८ करोड़ रु. दिये गये हैं ताकि वह निवासियों, विशेषकर महिलाओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण में सुधार करें, पर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

दिल्ली पुलिस के लंबे वार्षों के विपरीत की महिला सुरक्षा उनकी प्रमुख वित्ती है, यह जग जाहिर है कि उनमें से एक बड़ी संख्या वी.आई.पी. सुरक्षा पर तैयार रहती है। पर ऐसा पुलिस के कारण नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा पुलिस की संख्या न बढ़ाने तथा अन्य नीतिगत कारणों से है।

पिछले महीने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को महिलाओं को उचित सुरक्षा न उपलब्ध कराने के लिए फटकार लगाई थी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.टी.कैमरे (कैमरे) लगाए जाएं यदि सरकार, ओबामा की सुरक्षा ने किसी पर लॉक कर रही है। जनता में कई प्रस्तावों को आपराधिक व्यवहारों के लिए यह कैमरे की विवादित वाली सकती है। यह भी सरकार की स्वीकृति न होने के कारण है। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस यह दावा करती है कि वह महिलाओं की सुरक्षा को युद्ध स्तर पर प्राथमिकता दे रही है और स्पेशल कमिशनर, महिला सुरक्षा दीपक शर्मा ने पुलिस की योजनाओं की लंबी सूची का भी व्याख्यान किया कि ३,६३२ कैमरे — सीमा क्षेत्र और अदालत परिसरों को मिलाकर ८५ रुपयों पर लगाये हैं और सुरक्षित नगर परियोजना के अंतर्गत १३ स्थानों पर ६,६६६ कैमरे लगाने का कारण है। कैमरों के अलावा, शहर भर में ४०५ पैरिंग गेस्ट निवासों का सुरक्षा आकलन किये जाने को भी पुलिस एक उपलब्ध बता रही है।

बसों में भी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की विस्तृत योजना पुलिस द्वारा तैयार की गई थी। लेकिन, अब तक वे केवल २०० बसों में कैमरे लगाया सके हैं। सभी सार्वजनिक बसों और ऑटों में जी.पी.एस. लगाने की योजना भी अभी तक कामजों पर ही सीमित है। हालांकि, सभी नये ऑटो और बसों में जी.पी.एस. मशीनें लगाई गई हैं लेकिन इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए न तो कंट्रोल रूम है और न ही ८५ लाख पंजीकृत वाहनों को मॉनिटर करने के लिए पर्याप्त ट्रांसपोर्ट अधिकारी।

पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में अक्षमता का एक और कारण है पी.सी.आर. वैनों की संख्या की। दिल्ली में अनुगोदित वैनों की संख्या १००० है। इसमें से १५० वी.आई.पी. ड्यूटी पर लगे हुए हैं जबकि उन्हें बदलने का लिये जाना वाला एक वैन नहीं। इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए न तो कंट्रोल रूम है और न ही ८५ लाख पंजीकृत वाहनों को मॉनिटर करने के लिए एक साल ६७ पी.सी.आर. वैन मौजूद है।

जहाँ आम जनता की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए कैमरे लगाने हों या बेकार वाहनों को बदल कर नये वाहनों की खालीदारी करनी हो तो सरकार की स्वीकृति लेने और फिर इसके लिए वित्तीय और मानवीय सांसाधनों को आवंटित करने में महीनों और सालों लग जाते हैं। इसकी जावाबदी सरकार पर है जिसे अपनी जनता को अच्छी पुलिसिंग और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर समय उपाय युद्ध स्तर पर करना चाहिए।

(सौजन्यः न्यू इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, १३ मार्च २०१५)

**निर्भया कोष : उत्तराखण्ड पुलिस के लिए अर्थर्थीन**

वार्षिक बजट में निर्भया कोष की राशी